

प्रेषक,

डॉ० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग-02

देहरादून: दिनांक 10 नवम्बर, 2014:

विषय- दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-745/लेखा/दु0मू0प्रो0योजना पत्रा/2014-15, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम धनराशि रु0 28.75 लाख (रुपये अठाईस लाख पिछहत्तर हजार मात्र) विनियोजित किये जाने हेतु (चालू वर्ष के आय-व्ययक में कोई प्रावधान न होने के कारण) आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर संख्या तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जायेगी। प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अनिवार्यतः शासन/महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।
2. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग की दे दी जाय।
3. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय, साथ ही उत्पादकों को इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार आहरण किया जाय।
4. उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुरंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्य/मद पर सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुरंगत नियमों का अनुपालन किया जाय जाय।
5. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध उत्पादन हेतु प्रोत्साहन की धनराशि दुग्ध सहकारी समितियों के केवल अनुसूचित जनजाति के दुग्ध उत्पादकों को ही आवंटित की जायेगी। लाभान्वितों की सूची प्रत्येक वर्ष समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराते हुए वेब पोर्टल पर भी प्रदर्शित की जायेगी।
6. चूंकि प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में इस प्रयोजन हेतु कोई बजट व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि इस योजना हेतु व्यय तत्काल किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है। अतः श्री राज्यपाल महोदय रु0 28.75 लाख (रुपये अठाईस लाख पिछहत्तर हजार मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति/समायोजन आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 में कर ली जायेगी।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रथमतः-8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि से विनियोजन के नामे एवं अन्ततः अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डरी विकास-00-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-06-दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे खाला जायेगा। (Plan)

भवदीय,

(डॉ० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

वित्त विभाग-

संख्या-13/XXVII(1)/रा०आक०निधि०/2014 दिनांक

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एल० एन० पंत)
अपर सचिव।

संख्या- 70801/XV-2/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री, डेयरी को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य कौषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-4/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
7. कौषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड।
10. श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, एन०आई०सी० को उक्त योजनान्तर्गत वर्णित लेखाशीर्षक ऑन लाईन अंकित करने के संबंध में।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव।